संस्कृत शिक्षा और वैदिक ज्ञान के प्रसार की तैयारी

प्राचीन भारतीय ज्ञान नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए कई सिफारिशें कीं दूसरे संस्कृत आयोग ने

नई दिल्ली, 29 सितंबर (ईएनएस)। प्राचीन भारत की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए दूसरे संस्कृत आयोग ने संस्कृत का गौरव स्थापित करने और इस भाषा के प्रति लोगों की रुचि जाग्रत करने के लिए कई सुझाव दिए हैं। इन सुझावों में विशेष प्रयोगशालाएं स्थापित करने का सुझाव भी है, जहां विद्वान और वैज्ञानिक वैदिक प्रथाओं और अनुष्ठानों की वैज्ञानिकता को लेकर एक साथ अनुसंधान कर सकें। वर्षा कराने के लिए वैदिक यज्ञों, और यज्ञ-भस्म से उपचार के गुण जैसे कई अनुसंधान करने के सुझाव आयोग की ओर से सरकार को दिए गए है।

पहले संस्कृत आयोग का गठन 1956 में किया गया था। अब पद्म भूषण सत्यव्रत शास्त्री की अध्यक्षता वाले तेरह सदस्यीय आयोग ने स्कूली शिक्षा के लिए चार भाषी फार्मूला रखने का सुझाव भी दिया है। इस फार्मूले के तहत कक्षा छह से दस तक विद्यार्थियों के लिए संस्कृत पढ़ाने की अनुशंसा है। खास बात यह है यूपीए-द्वितीय के समय पिछले साल गठित दूसरे संस्कृत आयोग ने 460 पन्नों की यह रपट बीते माह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के समक्ष पेश की है। मौजूदा सरकार संस्कृत आयोग की इन सिफारिशों पर विचार कर रही है।

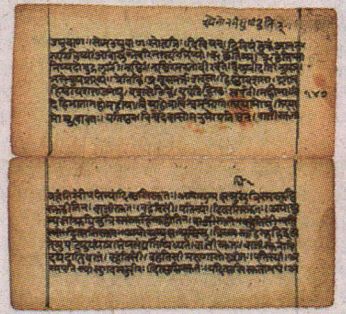

इस रपट का महत्त्वपूर्ण अंश प्राचीन वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में विद्यार्थियों को बताना है। इन सुझावों पर आयोग ने खास जोर दिया है। इस संदर्भ में आयोग ने सुझाव दिया है कि सभी विज्ञान और तकनीकी संस्थानों में संस्कृत परचों की आनिवार्यता रखी जाए। साथ ही इन संस्थानों में संस्कृत शिक्षकों को रखा जाए ताकि विषयों को स्पष्टता से समझा जा सके।

आयोग की रपट में कहा गया है कि इस समय कृषि विश्वविद्यालयों, वास्तुशिल्प और नगर-योजन संस्थानों, गणित संस्थानों, आइआइटी, आइएएम, विधि विद्यालयों में इस समय जो पढ़ाई हो रही है, वह केवल पाश्चात्य ज्ञान देने वाली है। इनमें अनुशासन का अभाव है। इस शिक्षा में प्राचीन भारतीय ज्ञान नहीं है। इन संस्थानों के विद्यार्थियों को नहीं पता चलता कि हमारे प्राचीन मनीषियों ने हजारों साल पहले किस तरह के ज्ञान का आविष्कार किया था।

आयोग की रपट में राजनीतिशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए प्राचीन भारतीय ग्रंथों-अर्थशास्त्र, शुक्र नीति, विदुर नीति और महाभारत के अध्ययन की सिफारिश की है ताकि उन्हें राजनीति और भारतीय मूल्यों का सही ज्ञान प्राप्त हो सके। आयोग ने रसायन शास्त्र के छात्रों के लिए रससारसमुच्चय और कृषि के लिए कृषिपाराशर और विकासायुर्वेद का अध्ययन कराने की सिफारिश की है, ताकि इस क्षेत्र में शोधित प्राचीन ज्ञान नई पीढ़ी तक पहुंच सके। आयोग ने कहा है कि

संस्कृत शिक्षा और वैदिक ज्ञान के प्रसार की तैयारी

इस ज्ञान से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास जागेगा और उन्हें अपने स्वर्णिम अतीत के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। आयोग की रपट में कहा गया है कि सरकार को प्राथमिकता के आधार पर इन सिफारिशों पर गौर करना चाहिए।

इस बारे में संपर्क करने पर सत्यव्रत शास्त्री ने ईएनएस को बताया कि यह रपट पहले संसद के पटल पर रखी जाएगी। इसके बाद इस पर खुली चर्चा हो सकेगी। इसलिए इस समय रपट पर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। मानव संसाधन मंत्रालय के प्रवक्ता घनश्याम गोयल ने ईएनएस की ओर भेजी गई प्रश्नावली पर कोई जवाब नहीं दिया।

दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर और संस्कृत भारती के अखिल भारतीय अध्यक्ष चांद किरण सलूजा ने कहा कि दूसरे संस्कृत आयोग ने तकरीबन वही सिफारिशें की हैं, जो 58 साल पहले गठित पहले आयोग ने की थीं।

उन्होंने कहा कि इस रपट के कई सुझावों पर पहले आयोग की रपट में चर्चा हो चुकी है। इस बात में कोई शक नहीं कि विज्ञान और तकनीकी संस्थानों में संस्कृत को उचित स्थान मिलना चाहिए। साथ ही हमारी शिक्षा नीति में इस भाषा का ध्यान रखा जाए तभी विद्यार्थियों को प्राचीन भारतीय ज्ञान मिल पाएगा। सलूजा सरकार की ओर से नियुक्त उस कमेटी के सदस्य हैं जिसे शिक्षा के लिए नई भाषा नीति तय करनी है।

दूसरे संस्कृत आयोग ने संस्कृत शिक्षा के लिए हर राज्य में एक स्कूल बोर्ड और विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश भी की है। साथ ही केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर केंद्रीय संस्कृत विद्यालय खोलने, निजी चैनलों और रेडियो स्टेशनों पर संस्कृत कार्यक्रम प्रसारित करने की सिफारिश की है।